



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931

No. 1433]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

का.आ. 2294(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 377(अ), तारीख 22 मार्च, 2006 द्वारा कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक तटीय जोनल प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. प्रधान सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार  | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव (पारिस्थितिकी और पर्यावरण), कर्नाटक सरकार  | —सदस्य   |
| 3. प्रधान सचिव, शहरी विकास, कर्नाटक सरकार  | —सदस्य   |
| 4. प्रधान सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन, कर्नाटक सरकार  | —सदस्य   |
| 5. प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य, कर्नाटक सरकार   | —सदस्य   |
| 6. प्रधान सचिव, सूचना, पर्यटन और युवा सेवाएं, कर्नाटक सरकार  | —सदस्य   |
| 7. अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य प्रदूषण बोर्ड, कर्नाटक सरकार   | —सदस्य   |
| 8. निदेशक, कर्नाटक राज्य दूर संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र, कर्नाटक सरकार   | —सदस्य   |
| 9. डॉ. एन. जयाबालान, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मत्स्य संसाधन और प्रबंधन विभाग, कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कालेज ऑफ फिशरीज, मैंगलोर | —सदस्य   |

10. प्रोफेसर के. वी. कृष्णामूर्ती, आचार्य और विभागाध्यक्ष, पादप विज्ञान, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली —सदस्य
11. श्री बी. के. जगदीश चन्द्र, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन रक्षक, बैंगलौर —सदस्य
12. श्री सुरेश हेबलीकर, इको वाच, पर्यावरण और अनुसंधान संवर्धन केन्द्र, बैंगलौर (गैर-सरकारी संगठन) —सदस्य
13. ज्येष्ठ निदेशक (तकनीकी), वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार —सदस्य-सचिव
- (II) प्राधिकरण, कर्नाटक राज्य के क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण क्वालिटी का संरक्षण और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :—
- (i) कर्नाटक राज्य से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तन या उपांतरण करने के लिए प्रस्तावों की परीक्षा और उसके लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिश करना;
- (ii)(क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट दशा में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्दिष्ट मामले में जारी किसी निदेश के असंगत न हों;
- (ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के अंतर्वर्तित उल्लंघनों वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणों सहित पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्दिष्ट करना;
- परंतु इस उप-पैरा के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय अथवा किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी;
- (iii) इस पैरा के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी निदेश के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवादें फाइल करना;
- (iv) इस पैरा के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
- (III) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विचार करेगा जो उसे कर्नाटक राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।
- (IV) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा ।
- (V) प्राधिकरण, अपरदन या अवक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा ।
- (VI) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
- (VII) प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, पैरा V, और पैरा VI के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को, परीक्षा और उनके अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- (VIII) प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जो कर्नाटक के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं ।
- (IX) प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- (X) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अधिवेशनों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित हैं ।

- (XI) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए होंगे।
- (XII) प्राधिकरण का मुख्यालय बेंगलूर में होगा।
- (XIII) ऐसे मामलों पर, जो विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण की परिधि और अधिकारिता के भीतर नहीं आता है, संबंधित कानूनी प्राधि- कारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

[ फा. सं. 12-4/2005-आईए-III ]

डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पण :**—कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन करने से संबंधित मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 21(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 377(अ), तारीख 22 मार्च, 2006 द्वारा उसका अंतिम पुनर्गठन किया गया।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****ORDER**

New Delhi, the 7th September, 2009

**S.O. 2294(E).**—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, Number S.O 377(E), dated the 22nd March, 2006, the Central Government reconstituted the Karnataka Coastal Zone Management Authority for a period of three years with effect from the date of publication of the order in the Official Gazette, and the term of the said Authority has been expired;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Karnataka Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, consisting of the following persons, namely :—

1. Principal Secretary, Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka —Chairman
2. Secretary, (Ecology and Environment), Government - of Karnataka —Member
3. Principal Secretary, Urban Development, Government of Karnataka —Member
4. Principal Secretary, Animal Husbandry and Fisheries, Government of Karnataka —Member
5. Principal Secretary, Industries and Commerce, Government of Karnataka —Member
6. Principal Secretary, Information, Tourism and Youth Services, Government of Karnataka —Member
7. Chairman, Karnataka State Pollution Control Board, Government of Karnataka —Member
8. Director, Karnataka State Remote Sensing Application Centre, Government of Karnataka —Member
9. Dr. N. Jayabalan, Professor and Head, Department of Fisheries Resources and Management, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore. —Member
10. Professor KV. Krishnamurthy, Professor and Head, Department of Plant Sciences, School of Life Sciences, Bharathidasan University, Tiruchirapalli —Member
11. Shri B.K. Jagadish Chandra, Retired Principal Chief Conservator of Forests, Bangalore —Member
12. Shri Suresh Heblikar, Eco-Watch, Centre for Promotion of Environment and Research, Bangalore (NGO). —Member
13. Senior Director (Technical), Department of Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka. —Member-Secretary

- II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Karnataka, namely :—

- (i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Karnataka State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;
  - (ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;
  - (b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :  
Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph may be taken up suo-moto or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;
  - (iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph;
  - (iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph.
- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Karnataka, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
  - IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
  - V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
  - VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
  - VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
  - VIII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Karnataka.
  - IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
  - X. The Authority shall ensure that at least two-third members of the Authority are present during the meetings.
  - XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
  - XII. The Authority shall have its headquarters at Bangalore.
  - XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No. 12-4/2005-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

**Note:** The principal order constituting the Karnataka Coastal Zone Management Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 21 (E) dated the 4th January, 2002 and last reconstituted *vide* S.O. 377 (E) dated the 22nd March, 2006.